

प्रेस विज्ञप्ति

‘राज्य में स्वास्थ्य बजट एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर परामर्श कार्यशाला’ जयपुर 29 मार्च 2016

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) द्वारा प्रयास संस्थान, चित्तोड़गढ व जन स्वास्थ्य अभियान के सहयोग से सहकारिता प्रबंध संस्थान (आई.सी.एम.), जयपुर मे राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ एक दिवसिय ‘राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बजट एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर परामर्श कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में राज्य आयोजना बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष प्रो. वी. एस. व्यास, प्रयास संस्थान, चित्तोड़गढ एवं जन स्वास्थ्य अभियान के डॉ. नरेन्द्र गुप्ता सहित विभिन्न संस्थाओं के करीब 55 प्रतिनिधी शामिल हुए। इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से राज्य में स्वास्थ्य बजट एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर किये गये अध्ययन के साथ राज्य में स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन एवं ढांचागत सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा की गयी।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में प्रो. वी. एस. व्यास ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाओं एवं सुविधाओं की गुणवत्ता बहुत कमझोर है जिसका प्रमुख कारण मानव संसाधनों की कमी के साथ संसाधनों एवं बजट का पूरा उपयोग भी नहीं हो पाना है। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं में काफी अंतर है। इसके अलावा प्रो. व्यास ने जोर दिया कि महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाएं जैसे- स्वास्थ्य एवं शिक्षा पूरी तरह सरकारी तंत्र द्वारा प्रदान की जानी चाहिये तथा इनको निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिये। डा. नरेन्द्र गुप्ता ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण तथा सरकार द्वारा लाये जा रही बीमा योजना के कारण होने वाली कठिनाईयों के बारे में बताया। डा. गुप्ता ने एन.एस.एस. के 2014 के आंकड़ों के हवाले से बताया कि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों या अस्पतालों पर ईलाज कराने वाले रोगियों की अपेक्षा निजी अस्पतालों में ईलाज कराने वालों को चार गुना अधिक खर्च करना पड़ता है जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिये पर्याप्त बजट नहीं देना है।

अगले सत्र में बार्क, प्रयास संस्थान तथा अन्य सस्थाओं द्वारा राज्य के चार जिलों में स्वास्थ्य बजट एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर किये गये अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों को पेश किया गया। इस अध्ययन के प्रमुख परिणाम निम्न हैं:

- पिछले कुछ वर्षों में राज्य में स्वास्थ्य बजट राज्य के कुल बजट का औसतन 5 प्रतिशत के करीब रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में हालांकि राज्य में स्वास्थ्य बजट बढ़ा है लेकिन आवंटित बजट की तुलना में खर्च लगभग हर वर्ष कम रहा है उदाहरण के लिये वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य पर कुल खर्च कुल आवंटित बजट का मात्र करीब 74 प्रतिशत रहा था।

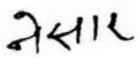
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कुल आवंटन तथा कुल खर्च में भी कमी आई है। मिशन होने के बावजूद इस योजना में भी खर्च आवंटन की तुलना में हमेशा कम होता है। वर्ष 2015-16 में भी दिसंबर तक कुल आवंटित बजट का मात्र 55 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है।
- राज्य की दो महत्वपूर्ण योजनाओं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बजट में भी विगत 3 वर्षों में भारी कटौती हुई है तथा इनका बजट 2014-15 की तुलना में 2016-17 में बहुत कम रहा है।
- यही स्थिति जिला पर भी देखने को मिली। झुंझुनूं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चुने हुये स्वास्थ्य केन्द्रों, विशेषकर जिला अस्पताल में कुल खर्च आवंटित बजट की तुलना में बहुत कम रहा है।
- इस अध्ययन में पाया गया कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन की भारी कमी है उदाहरण के तौर पर चित्तोड़गढ के जिला अस्पताल में 292 स्वीकृत पदों में से मात्र 153 पद भरे हुये हैं।

जन स्वास्थ्य अभियान की छाया पचोली ने प्रतापगढ जिले के 21 गांवों में चल रहे स्वास्थ्य सेवाओं के सामुदायिक निगरानी के बारे में बताया कि इस निगरानी से इन गांवों में ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिती सक्रिय हुई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है।

कार्यशाला में भाग ले रहे सहभागियों ने अपने क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिती के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने तथा ग्राम सभा की आगामी बैठकों में जन स्वास्थ्य के मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाने का संकल्प लिया तथा साथ ही कार्यशाला में उभरे सुझावों को एक मांग पत्र के रूप में राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात कही।

कार्यशाला के अंत में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र जयपुर के समन्वयक नेसार अहमद ने सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला का समापन किया।

धन्यवाद



नेसार अहमद
समन्वयक